RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-06
June-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

प्रधानमंत्री जनधन योजना : एक समीक्षात्मक अध्ययन

सुमन कुमार प्रेमी

शोध छात्र अर्थशास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 12 June 2019

Keywords
विकासशील देश राष्ट्रव्यापी वित्तीय

ABSTRACT

भारत एक विकासशील देश है। देश के आबादी का खास करके ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बैंकों की पहुँच से दूर है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा कई पहल की गई थी लेकिन यह वांछित परिणाम नहीं दे रही थी। देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन मिशन के तहत इस योजना का शुरूआत की गई। प्रधानमंत्री जन–धन योजना को देश भर में प्रत्येक घर में कम से कम एक बैंक खाता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ पेश किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में घरों की वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति की जाँच करना है। अध्ययन से पता चला कि प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि सरकार और बैंकों के निरंतर प्रयासों के कारण वित्तीय समावेशन के प्रति सकारात्मक दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी भारत में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए और भी अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

प्रस्तावनाः–

भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, लेकिन नीति–निर्माताओं के लिए यह बहुत चिंता का विषय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद देश की आबादी का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा बैंकों की पहुँच से दूर है। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी धन उधारदाताओं, जमींदारों, साहूकारों जैसे वित्त के पारंपरिक स्त्रोतों पर निर्भर है, जो ब्याज के ऊँची दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है तथा उनका शोषण करते हैं। इस तरह वित्तीय असमानता की खाई को और चौड़ा करता है तथा आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ालता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता दोनों अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए, वित्तीय समावेशन की पहचान विश्व बैंक द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों के रूप में की गई। इस प्रकार उन कमजोर समूहों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे उनकी बचत की आदतों को बढ़ाने में मदद मिले, पूँजी निर्माण में वृद्धि हो तथा गरीबी को दूर करने में मदद मिले। इस पृष्ठ भूमि में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्र व्यापी वित्तीय समावेशन मिशन के तहत 15 अगस्त 2014 को पेश किया गया तथा 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया। जिसका उद्देश्य प्रत्येक घर में कम से कम एक बैंक खाता और डेविट कार्ड मुहैया कराना, 10000 तक की ओवर ड्राफ्ट, दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना था।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति का अध्ययन करना।

इस योजना के अन्तर्गत विशेष लाभः–

1. जमा पर ब्याज।
2. 2 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा कवर।
3. कई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं।
4. पूरे भारत में धन का आसान हस्तांतरण।
5. सरकारी योजना के लाभार्थियों को इन खातों में प्रतयक्ष लाभ अंतरण।
6. 6 महीने खाते के संतोषजनक संचालन के बाद ओवर ड्राफ्ट की सुविधा।
7. प्रति घर केवल एक, वरीय घर की महिला के खाते में 10000 तक की ओवर ड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध।
8. यह योजना लाभार्थी की मृत्यु पर देय रूपये 30,0000/– का जीवन कवर प्रदान करती हे बशर्ते पात्रता शर्त को पूरा किया गया हो।
9. पेंशन, बीमा उत्पादों तक पहुँच।

इस खाते की सुविधाएँः–

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खोले गए सभी खाते शून्य बैलेंस खाते होंगे और रूपे डेबिट कार्ड से लिंक होंगे। खाता खोलने के लिए भावी खाता धारक को 'ग्राहक को जाने' यानि के0वाई0सी0 के कठिन अनुपालन की

RRIJM 2015, All Rights Reserved

आवश्यकता नहीं है। ग्राहक को सिर्फ एक तस्वीर और एक हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान की आवश्यकता होगी। इस योजना के तहत खोले गए खातों में एक साल में एक लाख रूपये से ज्यादा जमा नहीं किया जा सकता है। एक माह में 10,000 रूपये से जयादा की कुल निकासी नहीं की जा सकती है और खाते का बैलेंस 50,000 रूपये से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। यह खाता 12 महीने की अवधि के लिए क्रियाशील होगा। इस अवधि में खाता धारक को वैध पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड जमा करने होंगे। ऐसे मामले में खाता एक साल तक सक्रिय रहेगा।

समस्याएँ:–

1. नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याएँ
2. टेकनोलॉजिकल इश्यू
3. बैंकों के प्रति ग्रामीणों का रूझाव कम होना
4. बैंकिंग क्षेत्र में लैंगिक असमानता
5. जागरूकता की कमी।

योजना की प्रगति (अब तक):–

यह अध्ययन मुख्य रूप से डेटा के द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है, जो विशेष रूप से आर0बी0आई0 की वार्षिक रिपोर्ट, समितियों की रिपोर्ट, शोध पत्र, पत्रिकाओं, लेखों और वेबसाइटों आदि से एकत्र किए गए हें। इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। देश भर में कुल मिलाके 1.50 करोड़ बैंक खाते इस योजना के तहत पहले ही दिन खोले गए। 26 जनवरी 2015 तक लगभग 7.5 करोड़ परिवारों को बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध कराया गया। अप्रैल 2018 तक कुल 32.41 करोड़ बैंक खाते इस योजना के तहत खोले गए। 2018-2019 के प्रोग्रेश रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में कुल 37.30 करोड़ बैंक खाते इस योजना के तहत खोला गया है, जिसमें 29.66 सरकारी बैंकों के द्वारा 6. 37 ग्रामीण बैंक के द्वारा तथा 1.27 प्राइवेट बैंक के द्वारा खोला गया। कुल जमा 105523.30 करोड़ रूपया इस खाते में जमा हुआ जिसमें 83235.70 करोड़ रूपया सरकारी बैंकों के द्वारा, 19295.99 करोड़ रूपया ग्रामीण बैंक के द्वारा तथा 2991.62 करोड़ रूपया प्राइवेट बैंकों के द्वारा जमा स्वीकार किया गया। कुल 29.50 करोड़ डेबिट कार्ड उपलब्ध कराए गए जिनमें 24.48 करोड़ सरकारी बैंकों के द्वारा 3.86 करोड़ डेबिट कार्ड ग्रामीण बैंकों के द्वारा तथा 1.16 करोड़ डेबिट कार्ड प्राइवेट बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रगति रिपोर्ट निम्न तालिका से स्पष्ट कर रहे हैं।

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (Accounts Opened as on 12.01.2015)

Disclaimer : Information is based upon the data as submitted by different banks/SUBCs

S. No.		No. of accounts (In Lacs)			No. of Rupay Debit Cards (In Lacs)	Balance in Accounts (In Lacs)	No. of Accounts with Zero Balance (In Lacs)
		Rural	Urban	Total			
1.	Public Sector Banks	479.58	405.18	884.76	801.9	687477.33	635.9
2.	Regional Rural Banks	167.02	29.56	196.58	111.97	137598.95	147.95
3.	Private Banks	18.65	16.42	35.08	26.88	50932.99	23.12
	Total	**665.26**	**451.16**	**1116.42**	**940.75**	**876009.27**	**806.97**

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Pradhan_Mantri_Jan_Dhan_Yojana

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
(All figures in Crore)
Beneficiaries as 2018-2019

Bank Name / Type	Number of Beneficiaries at Rural/ Semiurban centre bank branches	Number of Beneficiaries at urban metro centre bank branches	No of Rural Urban Female Beneficiaries	Number of total Beneficiaries	Deposits in accounts (In Crore)	Number of Rupay Debit Cards issued to beneficiaries
Public Sector Banks	15.87	13.80	15.61	29.66	83235.70	24.48
Regional Rural Banks	5.18	1.19	3.56	6.37	19295.99	3.86
Private Sector Banks	0.71	0.55	0.68	1.27	2991.62	1.16
Grand Total	21.76	15.54	19.84	37.30	105523.30	29.50

Disclaimer : Information is based upon the data as submitted by different banks.

RRIJM 2015, All Rights Reserved

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन में महतवपूर्ण भूमिका अदा किया है।

निष्कर्षः–

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पिछले वर्षों की तुलना में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश में वित्तीय समावेशन की डिग्री में वृद्धि हुई है। वित्तीय समावेशन योजनाओं (FIP) को प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के प्रवेश में वृद्धि हुई, जिससे कमजोर समूहों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।

Reference

1. Anita,S. and Tapeja, S. 2015. Pradhan Mantri Jan Ghan Yojana: A Vehicle for Financial Inclusion, Indian Journal of Economics and Development, pp 499-508
2. Awasthi, A. Comprative Analysis of Pradhan Mantri Jan Ghan Yojana. Advances in Economics and Business Management 2015 pp 336-340
3. Economic Review, Ministry of Finance, Government of India
4. www.pmjdy.gov.in
5. www.financialservices.gov.in
6. www.hindustantimes.com
7. www.economictimes.com
8. Yojna magazine (monthly)
9. Census of India (2011)

RRIJM 2015, All Rights Reserved